नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

चिप निर्माण की ओर बढ़ते भारत के तेज कदम

भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की शुरुआत अब वैश्विक बाजार तक पहुंचने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन के अवसर पर देश की इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए ठीक ही कहा कि 2022 में शुरू हुई चिप निर्माण की यात्रा इतने कम समय में महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गई है. नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित कार्यक्रम में सूरत और मोहाली स्थित दो सेमीकंडक्टर कंपनियों के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत इस बदलाव का प्रमाण है. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़ी देश-विदेश की 300 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है. दरअसल,सेमीकंडक्टर आज आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद है. मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष तकनीक तक लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र चिप पर निर्भर है. ऐसे में भारत का चिप निर्माण में आगे बढ़ना केवल औद्योगिक विकास की उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है. दुनिया में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति कुछ प्रमुख देशों और कंपनियों तक केंद्रित रही है. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. भारत इस स्थिति में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है, तो उसे उत्पादन के साथ तकनीकी क्षमता और विश्वसनीय आपूर्ति का केंद्र भी बनना होगा.

प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले टेप-आउट शब्द का उदाहरण देकर इस क्षेत्र की निरंतर प्रगति का संदेश दिया. चिप का डिजाइन पूरा होने के बाद उत्पादन के लिए भेजना टेप-आउट कहलाता है, लेकिन इसके साथ काम समाप्त नहीं होता. अगली पीढ़ी की चिप के डिजाइन पर उसी समय काम शुरू हो जाता है. भारत का सेमीकंडक्टर मिशन भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है. पहले चरण का आकार आठ अरब डॉलर था, जबकि दूसरे चरण में 13.5 अरब डॉलर के निवेश का उल्लेख किया गया है. यह विस्तार बताता है कि सरकार इस क्षेत्र को तात्कालिक परियोजना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति के रूप में देख रही है. बहरहाल,भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह केवल चिप असेंबल करने या उत्पादन करने वाला देश बनकर न रह जाए. चिप डिजाइन, फैबलेस कंपनियों के विकास, बौद्धिक संपदा और अनुसंधान एवं विकास की क्षमता देश में ही विकसित करनी होगी. जिस देश के पास तकनीक और डिजाइन का स्वामित्व होता है, वही वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक मजबूत स्थिति बना सकता है. इसके लिए उच्चस्तरीय इंजीनियरिंग शिक्षा, कुशल मानव संसाधन, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, जल और बुनियादी ढांचे के साथ उद्योगों को लंबे समय तक नीति समर्थन देना होगा. भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है.सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वास्तविक भरोसा तभी कायम होगा, जब भारत की चिप गुणवत्ता, लागत और तकनीकी क्षमता के आधार पर वैश्विक कंपनियों की पसंद बने. निवेश घोषणाओं और उत्पादन केंद्रों से आगे बढ़कर निरंतर अनुसंधान, पेटेंट, निर्यात और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सफलता का पैमाना बनाना होगा. सेमीकंडक्टर मिशन भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर देता है. यह अवसर तभी स्थायी उपलब्धि में बदलेगा, जब निर्माण के साथ ज्ञान, डिजाइन और बौद्धिक संपदा का मजबूत आधार तैयार हो. वैश्विक बाजार तक पहुंची देश की चिप इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, मंजिल नहीं.

यूपीआई शुल्क ! अपेक्षित निर्णय, अनपेक्षित सवाल

राजीव खंडेलवाल

कभी जेब में नकदी न हो तो परेशानी होती थी. फिर आया यूपीआई— मोबाइल निकाला, क्यू आर कोड स्कैन किया और भुगतान हो गया. न छुट्टे की झंझट, न टॉफी वाला हाफ बार्टर सिस्टम, न बैंक जाने की जरूरत और न नकदी रखने की मजबूरी. देखते ही देखते यूपीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की 'धड़कन' बन गई.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस एक 'ऐप' नहीं पूरा 'भुगतान इकोसिस्टम' है. यह 'रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है', जिसके माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण संभव है. इसकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एनपीसीआई के अनुसार ही सिर्फ अगस्त 2026 में यूपीआई पर लगभग रिकार्ड 24.50 अरब लेन-देन (ट्रांजेक्शन) लगभग 29.82 लाख करोड़ मूल्य के हुए. इसे 11 देशों ने अभी तक अपनाया है. फलत: 'यूपीआई आज विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली है'. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह पहल जो उनकी श्रेष्ठ कार्य योजना में से एक है की असाधारण असफलता के लिये उन्हें हार्दिक बधाईयाँ.

2000 से कम का ट्रांजैक्शन बढ़ा तो खर्च भी बढ़ेगा

इसका प्रमुख कारण यूपीआई के विशाल डिजिटल ढांचे, साइबर सुरक्षा, तकनीकी विकास और भुगतान-इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से स्व-टिकाऊ बनाना बताया गया है लेकिन इसके लिए एमडीआर की कुल वसूली का केवल 5 प्रतिशत ही छोटे व्यापारियों में यूपीआई के विस्तार के लिए निर्धारित 'डेडिकेटेड फंड' में जाएगा. सरकार इस बात को भी भूल रही है कि लोग अब 10000 के भुगतान के लिए जब 2000 से कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ने (एक से पांच) से रखरखाव का खर्चा और बढ़ जाएगा.

'मुफ्त' सुविधा' अब 'सशुल्क' (अपवादों सहित)- 14 सितम्बर को जारी अधिसूचना द्वारा 15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई लेन-देन पर 2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी पर 0.4 प्रतिशत व्यापारी छूट दर लगेगा. 75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर इसकी अधिकतम सीमा 300 होगी. 'व्यक्ति-से-व्यक्ति' भुगतान और 2,000 तक के निर्धारित व्यापारी भुगतान पर शुल्क नहीं होगा. क्यूआर के माध्यम से प्रतिमाह 1 लाख तक प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारी एमडीआर से बाहर रहेंगे.

कुछ आवश्यक सेवाओं—जैसे रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम, बीमा और कुछ उपयोगिता सेवाओं—के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है, जिसमें निर्धारित परिस्थितियों में 5 का फ्लैट शुल्क होगा. पूंजी बाजार से जुड़े कुछ लेन-देन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती दर, (अधिकतम रु 300).

शुल्क ट्रांजैक्शन पर होना चाहिए राशि पर नहीं- एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है 0.4% की बजाय यदि प्रति ट्रांजैक्शन फ्लैट शुल्क लगाया जाता तो अधिक न्याय संगत होता. क्योंकि सर्वर, साइबर सुरक्षा और सेटलमेंट का खर्च लेन-देन की 'संख्या' पर आता है, उसकी राशि पर नहीं जिसकी पूर्ति के लिए यह शुल्क लगाया गया है.

96 प्रतिशत मुफ्त—लेकिन 4 प्रतिशत की कहानी बड़ी है- सरकार की ओर से यह जोर दिया जा रहा है कि जिन लोगों को छूट दी गई है वे लगभग 96% है और 2000 से अधिक के लेनदेन के मात्र 4% प्रतिशत व्यापारी ही एमडीआर की सीमा में आएंगे.

लेकिन उनका मूल्य पी2एम लेन-देन के कुल मूल्य का करीब दो-तिहाई है. यानी गिनती में चार प्रतिशत, मगर रकम (आकार) में लगभग 67 प्रतिशत. वित्तीय वर्ष 25-26 में यूपीआई के कुल 314 लाख करोड़ में से मात्र 104 करोड़ रु की राशि 96% की है, जबकि मात्र 4% का आकड़ा (आकार) 210 लाख करोड़ का है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस शुल्क से लगभग 15-20 हजार करोड़ का वार्षिक राजस्व का अनुमान है. एनसीपीआई के अनुसार 40% ग्राहक के बैंक 30% मर्चेंट के बैंक 20% यूपीआई के एप व 10% पेयर पीएसपी के जायेगा. अर्थात सरकार का सीधा राजस्व निरंक है. अगस्त 2026 में देश की संसद में पारित संशोधन कानून जिसके द्वारा यूपीआई पर शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खोला गया और अभी जब अधिसूचना जारी की गई, उसी समय अमेरिका की संसद में प्रेसिडेंट ट्रंप को 100% पेनल्टी लगाने का अधिकार प्रदान किया. भारत-अमेरिका के बीच फ्री व्यापार वार्ता (एफटीए) अंतिम दौर में है. इसमें एक मुद्दा हमारे भुगतान प्लेटफार्म 'मुफ्त' नहीं होना चाहिए, भी है.

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व

शुल्क आरोपण के समय का चुनाव सही नहीं, क्यों ?

प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस मनाने की जोर-शोर तैयारी के बीच अमित शाह द्वारा वर्ष 2029 के पूर्व तक समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूपीआई पर सेवा शुल्क लगाना समझ से परे है. औचित्य पूर्ण मानने के बावजूद जनता के बीच में ये कदम निश्चित रूप से 'अलोकप्रिय परसेप्शन व नरेशन' पैदा करेगा, जिनका सामना भाजपा को एक महीने चलने वाले जन्म दिवस कार्यक्रम में करना पड़ सकता है. अंतत: मुद्दा सिर्फ 0.4 प्रतिशत का नहीं है. बल्कि यह नीति की विश्वसनीयता का सवाल है. क्योंकि अभी भी अमेरिकन पेमेंट प्लेटफार्म मास्टरकार्ड, वीज़ा, अमेक्स (अमेरिकन एक्सप्रेस) गूगल पे, फोन पे आदि में लगने वाले शुल्क औसतन 2.35% की तुलना में यह बहुत कम है. यह डिजिटल इंडिया के भविष्य का सवाल है.

अब फिर बढ़ जाएगा नकदी का व्यवहार

भूल जाओ अच्छे दिन ! अब लौट आएंगे पुराने दिन, जब कहा जाता था आज नकद, कल उधार ! लोग यूपीआई चार्ज से बचने के लिए नकद रकम में लेन-देन करना पसंद करेंगे. कुछ व्यापारी भी अपनी दुकान या प्रतिष्ठान में बोर्ड लगा देंगे कि केवल कैश में पेमेंट स्वीकार किया जाएगा. सरकार ने पहले डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और जब देखा कि यह खूब फैल गया है तो इससे राजस्व कमाने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगा दिया. कपड़ा हो या किराना, एक बार की खरीद में 2000 से ऊपर ही खर्च होता है. टीवी, फ्रिज, जैसे व्हाइट गुड्स में भी यही बात है. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में 75,000 रुपये या उससे अधिक के व्यवहार में चार्ज 300 रुपये लगेगा. यदि इसे टालना हो तो लोग या तो डेबिट कार्ड के जरिए अथवा चेक पेमेंट करेंगे. क्यूआर कोड को मोबाइल दिखाने वाले आसान भुगतान से बचेंगे. जितना संभव होगा, उतनी नकद खरीदारी करेंगे. जहां मार्केट यार्ड हैं वहां रोज करोड़ों रुपये का लेन-देन होता है. एक खाते से दूसरे में रकम ट्रांसफर होती है. इसका व्यापार पर असर होगा, लेकिन व्यापारियों के सामने कोई विकल्प नहीं है. यदि वह नकद व्यवहार पर वापस जाते हैं तो कुछ बैंक उन पर डिपॉजिट चार्ज लगाएंगे. 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत चार्ज भी सालभर में बढ़कर काफी हो जाएगा. पहले ही हर वस्तु व सेवा पर जीएसटी लगा है. यह अतिरिक्त बला सामने आ गई. इस चार्ज की वजह से उनका मार्जिन और कम हो जाएगा. इस फैसले का व्यावहारिक परिणाम यह होगा कि टैक्स और चार्ज से बचने के लिए व्यापारी ग्राहकों को 'कैश डिस्काउंट' देंगे. सबसे बड़ा खतरा बैंकिंग प्रणाली पर होगा. अविश्वास के कारण वेतनभोगी मध्यम वर्ग महीने की शुरुआत में ही बैंकों से अपनी पूरी सैलरी नकद निकालकर घर में रख लेगा. इससे बैंकों में नकदी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा और देश वापस ब्लैक मनी के पुराने दौर में लौट जाएगा. देश और सरकार दोनों के हित में एकमात्र उपाय यही है कि इस फैसले को तुरंत खारिज किया जाए.

मध्य क्षेत्र की डायरी

ड्रोन से तालाब नापा... अब आई रसूख नापने की बारी

संदीप चंसौरिया

ड्रोन तीन दिन में वह काम कर गया, जिसे सरकारी तंत्र सालों में नहीं कर पाया. बड़े तालाब की हदें फिर सामने आ गईं और उसके आंचल में घुसे अतिक्रमण भी. अब नगर निगम को एनजीटी के सामने रिपोर्ट रखनी है. असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है. रिपोर्ट में अतिक्रमण दर्ज होंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई भी दर्ज होगी. क्योंकि, भोपाल के बड़े तालाब की कहानी में सीमांकन कोई नया अध्याय नहीं है. पहले भी हदें खिंचीं, मुनारें लगीं, अतिक्रमण चिन्हित हुए और एनजीटी ने आदेशों की झड़ी लगाई. जुलाई में एनजीटी ने छह साल तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी. अगस्त में सामने आया कि सात आदेशों के बावजूद कार्रवाई अधूरी है और 365 अतिक्रमणों का मामला अब भी अटका हुआ है. अब ड्रोन ने फिर तालाब का आईना सामने कर दिया है. सवाल यह है कि आईना दिखने के बाद चेहरा साफ होगा या आईना ही ढंक दिया जाएगा. एनजीटी ने इस बार केवल कागजी सीमांकन नहीं, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, जियो-टैगिंग और ग्राउंड ट्रूथिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों से वास्तविक एफटीएल तय करने को कहा है. साथ ही पहले से मौजूद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की समय सीमा भी तय की गई है. लेकिन, भोपाल में मुश्किल तालाब की सीमा खोजने की नहीं, रसूख की सीमा तय करने की है. जिन इलाकों में अतिक्रमण सामने आते हैं, वहां सवाल सिर्फ ईंट-पत्थर का नहीं होता. सवाल यह भी होता है कि निर्माण किसका है, अनुमति किसने दी, इतने साल तक किसकी नजर नहीं पड़ी और कार्रवाई की फाइल किस मेज पर जाकर सो गई. और, यहीं लोकतंत्र का सबसे असहज सवाल खड़ा होता है. अगर अतिक्रमण करने वाला कभी सत्ता के करीब था या आज सत्ता के करीब है, तो क्या बुलडोजर की रफ्तार बदल जाएगी. रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी भी आखिर उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिस पर कार्रवाई करनी है. इसलिए, जनता की दिलचस्पी सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, उसके अगले पन्ने में है. किस पर कार्रवाई हुई और किस पर नहीं हुई. बड़ा तालाब भोपाल की पहचान है. उसकी खूबसूरती का मतलब सिर्फ पानी का फैला हुआ विस्तार नहीं, बल्कि वह खुला आंचल है, जो शहर को सांस देता है. अगर उसकी हदों में आलीशान निर्माण, फार्म हाउस और दूसरे कब्जे टिके रहेंगे तो फिर हर साल सीमांकन का ड्रोन उड़ाना भी एक रस्म से ज्यादा क्या होगा. ड्रोन ने अपना काम कर दिया है. अब सरकारी मशीनरी तालाब की हद बचाती है या हद बचाने के नाम पर सिर्फ फाइल की हद तक ही कार्रवाई करती है, यह सीमांकन का सबसे अहम पहलू है, जिसका बड़ा तालाब के साथ-साथ भोजपालवासियों को भी इंतजार है.

बगैर मुखिया जनविश्वास सिर्फ रस्म अदायगी

जनता से सीधे संवाद का नाम 'जनविश्वास' रखा गया था. अब लगता है शुक्रवार तो वही है, संवाद भी वही है, बस शासन का हिस्सा कही अदृश्य होता दिख रहा है. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पिछले दो सप्ताह से व्यस्तता के चलते अभियान को समय नहीं दे पाए. छिंदवाड़ा से शुरू हुए अभियान का संदेश साफ था. हर शुक्रवार सरकार दफ्तरों की कुर्सियां छोड़कर जनता के बीच होगी. मुख्यमंत्री ने खुद शिकायतें सुनीं और मौके पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी की. सवाल यह नहीं कि मुख्यमंत्री हर शुक्रवार जिले में पहुंचें. यह व्यावहारिक भी नहीं. अभियान की पहचान तो तभी है जब मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में भी जिलों में मंत्री और अधिकारी जनविश्वास को बरकरार रखें, ना कि रस्म निभाएं. अभियान के पहले महीने में सरकार ने 5.64 लाख सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण का आंकड़ा जारी किया है. लेकिन, जनविश्वास सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनता, वरना इसका नाम जन-निराकरण अभियान रख दिया जाता. जनता को यह भरोसा चाहिए कि शुक्रवार कोई सरकारी कैलेंडर की खानापूर्ति नहीं, सचमुच सरकार के जनता के दरवाजे तक पहुंचने का दिन है. वरना डर यही है कि कहीं जनविश्वास धीरे-धीरे जन-विश्राम अभियान न बन जाए.

निशानेबाज

पाकिस्तान को हराना ही काफी, नापाक हाथों से नहीं लेते ट्रॉफी

पड़ोसी ने कहा 'निशानेबाज, हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा या टूर्नामेंट में उसे हराते हैं लेकिन इसके बाद उसकी टीम के सदस्यों से हाथ नहीं मिलाते और उसके खेल प्रमुख के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेते. उसका बहिष्कार कर देते हैं. यह कैसी नीति है? क्या इसे कहा जाए- गुड़ खाएं लेकिन गुलगुले से परहेज !' हमने कहा, 'हम जो करते हैं वह बिल्कुल सही है. पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कर पर्यटकों की हत्या की थी. इससे भारत में भारी रोष फैल गया. हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी करनी का फल चखा दिया. जिस देश के हाथ खून से रंगे हों, उनसे हमारे खिलाड़ी हाथ क्यों मिलाएं? पिछले साल एशिया कप की चैम्पियन बनने के बाद भी सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली हमारी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करने से भी मना कर दिया था. काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद नकवी हमारी वह ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान चले गए. ऐसा ही महिला क्रिकेट एशिया कप में भी हुआ. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम ने चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी महिला खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली.' पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, हमारे कबड्डी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाते हैं. स्क्वैश खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं. हॉकी टीम के खिलाड़ी हाई फाइव करते हैं. मुक्केबाज एक-दूसरे के ग्लव्स को टच करते हैं फिर क्रिकेट में ही ऐसा बहिष्कार हम क्यों करते हैं?' हमने कहा, 'बात यह है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. इसलिए हमारी क्रिकेट टीम उनका बॉयकाट करती है. बीसीसीआई देश में व्याप्त पाकिस्तान विरोधी भावनाओं का सम्मान करता है. हम जिस टूर्नामेंट में जीतें उसका प्रमुख कोई पाकिस्तानी हो तो हम उसके हाथ से ट्रॉफी लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. हम जीत गए और पाकिस्तान को धूल चटाकर चैम्पियन बन गए, इतना ही काफी है. ट्रॉफी लेना जरूरी नहीं है. ट्रॉफी से बड़ी देशभक्ति है.'

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर 12384

- डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3		■	4	■	5
6			■	■	7		
	■	8	9			■	
10	11			■	■	12	■
■		■	13		14		15
16				■		■	
17		■	■	18			
	■	19				■	

उसका फल 2. मवाद, पीब (अं), अतः, पीछे3. यमपुर (सं.) 4. जो जाग रहा हो, सजग, वह अवस्था जिसमें सब बातों का परिज्ञान होता रहता है 5. कौटिल्य 9. पितृपक्ष, श्राद्ध 11. पश्चाताप 12. रास्ता, मार्ग, पथ, बाट (उर्दू) 14. जो अपने मान इज्जत या प्रतिष्ठा को ही धन समझता हो 15. मंद गति से भ्रमण करना 16. कष्ट, पीड़ा 18. काबू, अधिकार में करना, बस (सं.)

बाएं से दाएं

1. बदनामी, अपकीर्ति (सं.) 6. पति, स्वामी 7. सूर्य या चंद्र का पूरे या किसी अंश में पृथ्वीवासियों को दिखाई न देना 8. जनसाधारण में प्रचलित गीत 10. बूंद-बूंद करके गिरना 13. गर्मी, उष्णता 16. यात्रियों या माल का गमनागमन 17. लोहे का वह छिछला गोल बर्तन जिस पर रोटी सेंकते हैं 18. वह स्थान जहां प्राणदंड दिया जाए (सं.) 19. वाटिका

ऊपर से नीचे -

1. एक वृक्ष तथा कड़े छिलके वाला

Solution 12383

पु	ष्प	क	■	ह	र	द	म
त	■	स	ला	ह	■	ह	स्ती
ला	य	क	■	र	मे	श	■
■	द्य	■	आ	■	वा	त	ज
क	पि	ल	दे	व	■	■	न
र्म	■	■	श	ह	र	या	र
ठ	न	क	■	श	■	त	व
ता	ली	म	■	त	ल	ना	■

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में भौतिक सुखों की प्राप्त होगी. मन में उत्साह बना रहेगा. मित्र के सहयोग से व्यापार में लाभ होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. वर्ष के मध्य में दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा. व्यक्तित्व में सुधार होगा. शिक्षा में व्यवधान आयेगा. वर्ष के अन्त में दौड़धूप होगी. मित्र से विवाद हो सकता है. मतभेद में वृद्धि होगी. अचानक धन लाभ का योग है. मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद होगा. धार्मिक कार्यो में संलग्नता रहेगी. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को दौड़धूप की अधिकता रहेगी. अचानक धन लाभ का योग है. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को धार्मिक कार्यो में संलग्नता रहेगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को खानपान पर संयम रखना हितकर रहेगा. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को राजनीति में विशेष सतर्कता बांछनीय. कर्क राशि के व्यक्तियों को निजी कार्यो में व्यस्तता रहेगी.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक स्वस्थ्य, सुन्दर, हष्टपुष्ट, मिलनसार, धार्मिक, प्रवृत्ति का होगा. क्रोध की भावना अधिक रहेगी. शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेगा. माता पिता का विशेषभक्त होगा. प्रवास का शौकीन होगा. मनोरंजन, आमोद प्रमोद का शौकीन होगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

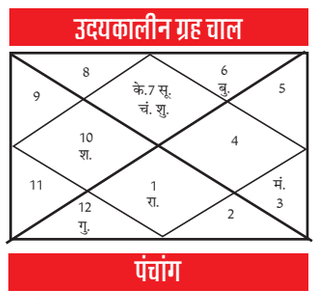

पंचांग

रा.मि. 28 संवत् 2083 भाद्रपद शुक्ल अष्टमीं शनिवासरे दिन 2/19, मूल नक्षत्रे रात 1/48, आयुष्मान योगे दिन 3/53, वव करणे सू.उ. 5/57, सू.अ. 6/3, चन्द्रचार धनु, शु.रा. 9,11,12,3,5,7 अ.रा. 10,1,2,4,6,8.

शुभांक- 2,4,8.

व्यापार भविष्य

भाद्रपद शुक्ल अष्टमीं को मूल नक्षत्र के प्रभाव से गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, के भाव में मंदी होगी. गुड़ खांड़ शक्कर, कालीमिर्च, धनियां, बादाम, लहसुन, प्याज, अदरक, के भाव में तेजी होगी. सरसों, अलसी, अरंडी, के भाव में नरमी रहेगी.

भाग्यांक 8065 है.

मेष- कार्य क्षेत्र में लाभ होगा. नये मैत्री संपर्क स्थापित होंगे, पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी.

वृषभ- शत्रु बाधा दूर होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

मिथुन- मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विरोधी वर्ग सक्रिय रहेंगे. धार्मिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा.

कर्क- आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी. यात्रा में सावधानी व सतर्कता बांछनीय है. नवीन कार्यो में विचार विमर्श होगा.

सिंह- उदर विकार तथा रक्त पीड़ा से तकलीफहो सकती है. सोचे हुये कार्यो में अनावश्यक विरोध हो सकता है.

कन्या- नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. दिनचर्या नियमित रहेगी.

तुला- कोर्ट कचहरी आदि के कार्यो में सफलता मिलेगी. निजी दायित्वों की पूर्ति होगी. परिश्रम अधिक करना होगा.

वृश्चिक- संतान के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी. वाणी कटुता आपके कार्य में व्यवधान कर सकती है. संयम से कार्य करें.

धनु- रक्त संबंधियों, पड़ोसियों से संतुलित संभाषण हितकर रहेगा. पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी.

मकर- कार्य व्यस्तता अधिक रहेगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. प्रिय संदेश प्राप्त होगा.

कुम्भ- नये संबंधों का लाभ होगा. मांगलिक कार्यो पर विचार होगा. परिश्रम की अधिकता रह सकती है.

मीन- किसी अधिकारी के कारण मानसिक तनाव रह सकता है. समझौता की नीति अपनाने से लाभ होगा.

SUDOKU 7516

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7515

8	2	4	3	9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1